रेल बजट 2013-14 की मुख्य बातें

(

महत्वपूर्ण क्षेत्र

1. संरक्षा; 2.सुदृढ़ीकरण; 3. यात्री सुविधाएं; 4.वित्तीय अनुशासन.

कुछ उपलब्धियां/पहल

- भारतीय रेल 'वन बिलियन के विशिष्ट क्लब' में सम्मिलित हो गई है, इस क्लब में अब तक चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की रेल ही शामिल थी;
- भारतीय रेल 10000 टन भार से अधिक टन भार वाली मालगाड़ियां चलाने वाले देशों में भी शामिल हो गई है;
- टैरिफ को ईंधन के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से जोड़ते हुए 'ईंधन समायोजन घटक' अवधारणा कार्यान्वित की जाएगी;
- वर्ष 2013-14 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रेल भूमि विकास प्राधिकरण और भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम के लिए 1000-1000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
- डीएफसी के लिए विश्व बैंक और जेआईसीए के ऋणों के लिए एक नई निधि-डेट सर्विस फंड- की स्थापना ऋण संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने और भविष्य की अन्य दायिताओं के लिए की जाएगी।

संरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने के उपाय

- दस वर्षों (2014-2024) की अवधि के लिए एक समवेत् संरक्षा योजना बनाना।
- 12वीं योजना के दौरान 10,797 समपारों को समाप्त करना और भविष्य में भारतीय रेल प्रणाली में कोई नया समपार नहीं बनाना।
- स्वचालित ब्लॉक सिगनल सिस्टम पर ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली की शुरूआत करना।
- देश में विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का गहन परीक्षण करना।
- 60 किग्रा. वाली पटरियों, 260 मीटर लंबे रेल पैनलों तथा बेहतर फ्लैश बट्ट वेल्डिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए रेलपथ संरचना को अपग्रेड करना।
- 160/200 किलोमीटर/प्रति घंटे की गति वाली सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत गाड़ियों की शुरूआत करना।
- एन्टी क्लाइम्बिक फीचर वाले टक्कर-रोधी एलएचबी सवारी डिब्बे की शुरूआत करना।
- अगले एक वर्ष में 17 पहचाने गए डिस्ट्रैस्ड पुलों का पुनर्स्थापन करना।
- काम्प्रिहेंसिव फायर एण्ड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करना।
- सभी गाड़ियों के गार्ड एवं ब्रेक वैन, वातानुकूलित कोचों और पैन्ट्री कारों में पोर्टेबल अग्निशामकों की व्यवस्था करना।
- कोचों में अग्निरोधी फर्निशिंग सामग्रियों का प्रयोग करना।
- हाथियों से संबंधित दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उपाय शुरू करना।
- रेल यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से रेल सुरक्षा बल महिला कार्मिकों की चार कंपनियों का गठन किया गया है तथा आठ अतिरिक्त कंपनियां गठित की जाएंगी।

- रेल सुरक्षा बल में भर्ती करना, जिसमें से 10% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

रेल पर आधारित उद्योग

स्थापित की जाने वाली नई फैक्टरियां/कारखाने:

- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सहयोग से राय बरेली में एक नई फॉर्ज्ड व्हील फैक्टरी।
- राज्य सरकार और भेल (बीएचईएल) के सहयोग से भीलवाड़ा (राजस्थान) में ग्रीनफील्ड मेनलाइन इलैक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट्स (मेमू) विनिर्माण इकाई।
- राज्य सरकार के सहयोग से जिला सोनीपत (हरियाणा) में कोच विनिर्माण इकाई।
- राज्य सरकार के सहयोग से कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) में मिडलाइफ पुनर्स्थापन कारखाना।
- बड़ी लाइन के मालडिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए बीकानेर और प्रतापगढ़ में कारखाने।
- मिस्रोड (मध्य प्रदेश) में मोटराइज्ड बोगियों की मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए कारखाना।
- कालाहांडी (ओडिशा) में नया मालडिब्बा अनुरक्षण कारखाना।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) के माध्यम से चंडीगढ़ में आधुनिक सिगनलिंग उपस्कर कारखाना।

हरित पहल

- सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता का उपयोग करने के लिए रेल ऊर्जा प्रबंधन कंपनी (आरईएमसी) की स्थापना करना।
- 75 मेगावॉट की क्षमता वाले पवन चक्की संयंत्रों की स्थापना करना और 1000 समपारों को सौर ऊर्जा से ऊर्जित करना।
- नई पीढ़ी के ऊर्जा कुशल विद्युत रेलइंजनों तथा ईएमयू का उपयोग करना।
- कृषि-आधारित और रि-साइकिल किए गए कागज का अधिक उपयोग करना और खान-पान में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।

यात्रियों/रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं

- साफ-सफाई से जुड़े तमाम पहलुओं पर तत्काल ध्यान देने के लिए 104 महत्वपूर्ण स्टेशनों की पहचान करना।
- गाड़ियों में जैविक शौचालयों की उत्तरोत्तर व्यवस्था करना।
- यंत्रीकृत सफाई सुविधाओं के साथ प्लेटफार्मों पर कंक्रीट एप्रनों की व्यवस्था करना।

- ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम और क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम का और अधिक स्टेशनों एवं गाड़ियों में विस्तार करना।
- अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटिड टिकट वेंडिंग मशीनों (सीओ-टीवीएम) और जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) योजना का विस्तार करना।
- विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना करना।
- चुनिंदा गाड़ियों में एक ऐसी पायलट परियोजना शुरू करना जिससे यात्री कोच की सफाई और रियल टाइम फीडबैक के संबंध में एसएमएस/फोन कॉल और ई-मेल के जरिये ऑन बोर्ड कर्मचारियों से आसानी से संपर्क कर सकें।
- लिनेन की बेहतर धुलाई के लिए 8-10 और यंत्रीकृत लांड्रियां स्थापित करना।
- गाड़ियों में उदघोषणा सुविधा और इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्डों का प्रावधान करना।
- कई गाड़ियों में नि:शुल्क वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- पहले से चुने गए 980 स्टेशनों के अतिरिक्त 60 और स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करना।
- रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेना।
- उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनी गई गाड़ियों में एक सवारी डिब्बे – 'अनुभूति' की शुरूआत करना।
- वृद्ध व्यक्तियों और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के लिए ए-1 और अन्य बड़े स्टेशनों पर 179 एस्केलेटरों और 400 लिफ्टों की व्यवस्था की जाएगी।
- अधिक से अधिक स्टेशनों पर शौचालयों सहित सवारी डिब्बों के लेआऊट को दर्शाने वाले ब्रेल स्टिकरों को चिपकाना, व्हील चेयरों और बैटरी चालित वाहनों की व्यवस्था करना तथा सवारी डिब्बों को व्हील चेयर के अनुकूल बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ जेटीबीएस आरक्षित करना।
- तत्काल योजना सहित आरक्षित टिकटों में कदाचार को रोकना।
- तीसरी पार्टी द्वारा लेखा परीक्षा और भोजन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भोजन जांच प्रयोगशालाओं के साथ समझौता करना; रेलवे परिसरों में आईएसओ प्रमाणित अत्याधुनिक बेस किचन स्थापित किए जाएंगे।
- एक टोल फ्री नंबर (1800 111 321) के साथ केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना करना।

रेल पर्यटन

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से मल्टी-मोडल ट्रेवल पैकेज की शुरूआत करना।
- रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल द्वारा यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए 'यात्रा पर्ची' जारी करना।

- स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के लिए रियायती किरायों पर 'आजादी एक्सप्रेस' नामक एक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी की शुरूआत करना।
- 7 और स्टेशनों यथा बिलासपुर, विशाखापट्नम, पटना, नागपुर, आगरा, जयपुर और बेंगलूरू पर एक्जीक्यूटिव लाउंज शुरू करना।

सूचना प्रौद्योगिकी पहल

- यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं में '**आधार**' का उपयोग करना।
- 0030 बजे से 2330 बजे तक इंटरनेट टिकटिंग।
- मोबाइल फोन द्वारा ई-टिकटिंग।
- आरक्षण की स्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी देने के लिए एसएमएस अलर्ट योजना।
- रियल टाइम सूचना प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक गाड़ियों को शामिल करना।
- इंटरनेट रेल टिकटिंग में नेक्सट जनरेशन ई-टिकटिंग प्रणाली।
- नेक्सट जनरेशन ई-टिकट प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे इस समय के प्रति मिनट 2000 की तुलना में 7200 टिकटों को जारी किया जा सकेगा तथा इस समय के एकसाथ 1.20 लाख उपयोगकर्त्ताओं की तुलना में इससे 40,000 रेल उपयोगकर्त्ताओं को हैंडल किया जा सकेगा।

वित्तीय प्रदर्शन 2012-13

- लदान का संशोधित लक्ष्य 1007 मिलियन टन है, जबकि यह बजट अनुमान में 1025 मिलियन टन था।
- सकल यातायात प्राप्तियों को संशोधित अनुमानों में 1,25,680 करोड़ रुपए किया गया। इसे बजट अनुमानों की तुलना में 6,872 करोड़ रुपए कम किया गया है।
- साधारण संचालन व्यय को 84,400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के स्तर पर रखा गया; पेंशन भुगतानों को 1,500 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रूपए किया गया।
- सरकार की लाभांश दायिता को पूर्ण रूप से निपटाया जाना है।
- 15,557 करोड़ रुपए की बजट राशि की तुलना में 10,409 करोड़ रुपए का आधिक्य।
- 2011-12 में लिए गए 3,000 करोड़ रुपए के ऋण को ब्याज सहित पूरी तरह चुका दिया गया है।
- परिचालन अनुपात 2011-12 के 94.9% की तुलना में 88.8% रहा।

बजट अनुमान 2013-14

- 1047 मिलियन टन का माल यातायात लदान, 2012-13 से 40 मिलियन टन अधिक।
- यात्री वृद्धि – 5.2%
- सकल यातायात प्राप्तियां – 1,43,742 करोड़ रुपए अर्थात् 2012-13 के बजट अनुमान की तुलना में 18,062 करोड़ रुपए की वृद्धि।
- साधारण संचालन व्यय – 96,500 करोड़ रुपए।
- मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 7,500 करोड़ रूपए और पेंशन निधि में 22,000 करोड़ रुपए का विनियोजन।
- 6,249 करोड़ रुपए के लाभांश के भुगतान का अनुमान।
- परिचालन अनुपात 87.8% किया जाना है।
- निधि शेष 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा।

वार्षिक योजना 2013-14

- 63,363 करोड़ रुपए का अब तक का उच्चतम योजना परिव्यय।
    - सकल बजटीय सहायता – 26,000 करोड़ रुपए
    - रेलवे संरक्षा निधि – 2,000 करोड़ रुपए
    - आंतरिक संसाधन – 14,260 करोड़ रुपए
    - ईबीआर- बाजार से ऋण – 15,103 करोड़ रुपए
    - ईबीआर- पी पी पी – 6,000 करोड़ रुपए।
- 2013-14 में 500 किमी नई लाइन, 750 किमी दोहरीकरण, 450 किमी आमान परिवर्तन का लक्ष्य।

वित्तीय अनुशासन

- संसद के मॉनसून सत्र अथवा शीतकालीन सत्र में अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत नहीं की गई;
- 3,000 करोड़ रुपए के ऋणों का पूर्ण भुगतान किया गया;
- 347 परियोजनाओं को सुनिश्चित वित्त पोषण के साथ प्राथमिकता;
- परिचालनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं और अंतिम चरण वाली परियोजनाओं के लिए उदार वित्त पोषण प्राप्त करना;
- प्रतिबद्ध दायिताओं को पूरा करने के लिए नए फंड- डेट सर्विस फंड की स्थापना;
- चल स्टॉक के अनुरक्षण और ईंधन खपत में कुशलता लाने के लिए कठोर लक्ष्य निर्धारित करना;
- 12वीं योजना के अंतिम वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए के निधि शेष के सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।

कर्मचारी कल्याण

- कर्मचारी क्वार्टरों के लिए निधि आबंटन बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए किया गया है।
- सभी मंडल मुख्यालयों पर अकेली रहने वाली महिला रेल कर्मचारियों के लिए हॉस्टल सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- सभी ऐसे शहरों में जहां अस्पताल या तो सीजीएचएस के साथ या रेलवे के साथ पैनलबद्ध हों वहां आरईएलएचएस के लाभार्थियों को मेडिकल इमरजेन्सी के समय इलाज की सुविधा प्रदान करना।
- रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के बैरकों की स्थिति में सुधार लाना।
- लोको-पायलटों को तनाव न हो इसके लिए लोकोमोटिव कैबों में वाटर क्लोसेट्स और एयर कंडीशन की व्यवस्था करना।

प्रशिक्षण और भर्ती

- इस वर्ष 1.52 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसमें से 47,000 रिक्तियां कमजोर वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई हैं।
- 25 स्थानों पर रेल संबंधी व्यवसाय में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- रेल संबंधित इलैक्ट्रॉनिक टैक्नोलॉजी में प्रशिक्षण देने के लिए नागपुर में एक बहु-विभागीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान (आईआरआईएफएम) एक विशिष्ट केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- एम. फिल और पीएच.डी. स्तरों पर भारतीय रेल से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन और शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पांच फेलोशिप दिए जाएंगे।
- कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए रेल से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टेरी (TERI) मे पीठ की स्थापना।

खेल-कूद

- रेलवे की टीमों ने 2012 में 9 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती।
- रेलवे खेल-कूद संवर्धन बोर्ड को 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2012' से सम्मानित किया गया।

रियायतें

- राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्ध कराना, जो फर्स्ट क्लास/सैकंड एसी में यात्रा के लिए मान्य होगा।
- ओलंपिक पदक विजेताओं एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यात्रा करने के लिए मानार्थ कार्ड पास प्रदान किया जाएगा।
- खिलाड़ियों को दिए गए सभी कार्ड पासों, जिनसे वे राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं, पर अब उन्हें दुरांतो गाड़ियों में भी यात्रा करने की अनुमित होगी।
- महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के विजेता, यदि अविवाहित हो तो उनके मरणोपरांत उनके माता-पिता को फर्स्ट क्लास/सैकंड एसी में वैध मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान करना।
- पुलिस पदक विजेताओं को वर्ष में एकबार राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में सैकंड एसी में एक सहचर के साथ यात्रा के लिए मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- स्वतंत्रता सेनानियों के पासों का तीन वर्ष में एकबार नवीकरण किया जाएगा।

गाड़ियां

- 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाएंगी।
- 26 नई पैसेंजर सेवाएं, 8 डेमू सेवाएं और 5 मेमू सेवाएं चलाई जाएंगी।
- 57 गाड़ियों के चालन का विस्तार किया जाएगा।
- 24 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जाएगी।

महानगर परियोजनाएं/उपनगरीय सेवाएं

- 2013-14 में मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में प्रथम एसी ईएमयू रेक की शुरूआत करना।
- मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू करना।
- कोलकाता में 80 सेवाओं और चेन्नै में 30 सेवाओं में रेकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार की गई है।

टैरिफ प्रस्ताव

- रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस पर अंतर-मंत्रालय स्तर पर परामर्श किया जा रहा है।
- फ्रेट टैरिफ के संबंध में ईंधन समायोजन घटक (एफएसी) से संबद्ध संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से लागू किया जाएगा।
- सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्काल प्रभार में मामूली वृद्धि की गई है।
- संवर्धित आरक्षण शुल्क को समाप्त किया गया है।

*****